

[Dr. Subramaniam Swamy]

Recently a JNU professor objected to the *locus standi* of Shri Morarji Desai enquiring into malpractices during the emergency in Universities. This should have been welcomed because of Morarji Bhai's moral stature and also he has long experience as Chancellor of Gujarat Vidyapith.

Now, Sir, what these professors really object to is that having padded their nests by their disgraceful collaboration with the previous dictatorial regime, they are to face an exposure of their own lack of academic standing. This has obviously made them insecure. They can no more assume that they can live comfortable luxurious lives without fear of accountability.

Sir, the cry of autonomy of Universities should not be a cover for unlimited freedom to run Universities as mini-kingdoms for a few feudal-lords posing as academicians.

However, having said this, I would also like to draw the Prime Minister's attention through you to the fact that a proper enquiry of the Universities is being impeded by the control of information flowing to him. This control is being exercised by an unholy alliance of discredited University professors and the corrupt administrators both in the Universities and in the Education Ministry.

I would like to give you an illustration. The Prime Minister enquired into the matter regarding the IIT, Delhi and all the people who are supplying him the files from the Education Ministry are people who have their sons and daughters studying in the IIT and whose admission, was made available by very dubious means.

Sir, this clearly shows that because of this kind of collaboration interests and conflict of interest, it is not possible for the Prime Minister to get a proper, uninterrupted and unadulterated flow of all information.

Therefore, Sir, a proper enquiry by the Prime Minister of these Universities must be preceded by a purge or a major re-shuffle of University administrators both in the Universities and in the Ministry of Education.

(iv) REPORTED DAMAGE TO CROPS DUE TO RECENT HEAVY HAILSTORMS IN DIFFERENT PARTS OF THE COUNTRY

श्री मनिराम बालुकी (मधुरा) :

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस जगह से यहाँ आ रहा हूँ वह स्थान मधुरा भारत में किसानों का प्रतीक है। वहाँ गोपाल कृष्ण हलधर थे। अमल में भारत किसानों का देश है। जब किसानों पर आपत्ति आई, तो राजा जनक ते हल चलाया। भगवानकृष्ण गोपाल-हलधर-ने भी न सिर्फ हल चलाया, बल्कि गड्यें चराई और गोबर्देन को उठा कर उस क्षेत्र को बाढ़ से बचाया। उस के बाद समय समय पर महात्मा गांधी, डा० मोहिबा, श्री जयप्रकाश नारायण और आज के गण्डुपति किसानों के लिए संघर्ष करते रहे हैं। किसान ममस्त भारत का प्रतीक है। लेकिन वह कितना अभाग्य है कि हालांकि जनता पार्टी और विपक्ष दोनों ही किसानों की शक्ति के बल पर यहाँ बैठते हैं, लेकिन किसानों के दर्द की बात यहाँ नहीं उठाई जाती है। अगर किसानों के दर्द की कोई बात यहाँ उठाने की कोशिश की जाती है, या उठाई जाती है, तो जो लोग किसानों की शक्ति के द्वारा यहाँ आये हैं, वे कहते हैं कि किसानों की बात यहाँ न उठाई जाये।

जब जनता पार्टी का शासन आया, तो इस देश में एक बहुत बड़ी कान्ति हुई, एक नानाशाह खत्म हुआ और जनतंत्र का जन्म हुआ। लेकिन दुर्भाग्य से इन्द्र का कोप हुआ और देश में बाढ़ की विपत्ति आई। शासन ने इस बारे में बहुत काम किया, जिस से लोगों को कुछ राहत मिली, लेकिन जितना काम करना चाहिए, उतना नहीं हुआ। इस के बाद

किसानों के लिए गन्ने, कपास, सरसों और गुड़ और शेर के भाव की समस्या पैदा हुई। अब ओलावृष्टि से, जिसे उर्दू में जालाबारी कहते हैं, किसानों की समस्त फसल खराब हो गई है।

कृषि मंत्री खुद किसान हैं और किसानों के प्रतिनिधि हैं। यह सदन भी किसानों का प्रतिनिधि है। अच्छा होता कि इस सवाल पर यहां बहस की जाती। अगर ऐसा होता, तो हिन्दुस्तान के किसानों के दर्द के लिए वह एक फाहे का काम देती और किसान यह महसूस करते कि यह सदन हमारे ग्राम में शरीक है और वह हमारे दर्द पर सहानुभूति से विचार कर रहा है। कम से कम यह भावना तो होती कि जालाबारी या ओला-वर्षा से किसानों का जो नुकसान हुआ है, उस के पलिए कुछ मुआवजा दिया जाये। हम उन्हें बीमे की कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सके हैं, जबकि कारों वगैरह के लिए, और कारखानेदारों को, यह सुविधा मिली हुई है।

किसान बेचारे अनपढ़ हैं। लेकिन गांधी जी के सपनों के मुताबिक और डा० लोहिया के शब्दों में कभी वह दिन आयेगा, जब भारत का किसान उठेगा और अपनी किस्मत का फसला खुद करने के काबिल होगा, और तब इस सदन के माननीय सदस्य भी भाग भाग कर उस का काम करेंगे। अच्छा होता कि कृषि मंत्री कम से कम यह ऐलान तो करते कि किसानों को जाला बारी या ओला-वृष्टि से जो नुकसान हुआ है, उस का मुआवजा दिया जायेगा।

हमारे विरोधी भाई बोलने में कम नहीं हैं। मुझे खुशी है कि वे बोलते तो बहुत हैं। लेकिन वे कभी एक मेम्बर की, और कभी दूसरे मेम्बर की, जूठी थाली उठा कर भागते हैं, और उसी में खाना शुरू कर देते हैं।

लेकिन वह बुनियादी सवालों—किसानों, मजदूरों और शरीबों के सवालों—को नहीं लेते हैं। अगर इस हाऊस में बुनियादी सवालों को लिया जायेगा, तभी देश और लोकतंत्र मजबूत होगा। अगर विरोधी लोग बुनियादी सवालों को उठाएँ, तो मुझे खुशी होगी, जैसा कि हम लोग उठाया करते थे। लेकिन दूसरों के सवालों को उठाना, किसी के गीत गाना और किसी की टांग खींचना ठीक नहीं है।

मैं कृषि मंत्री से बड़े पुरजोर शब्दों में अनुरोध करूंगा कि वह कानून की दलदल में न फसें। वह बाबा नानक के अनुयायी हैं, जिन्होंने बुढ़ापे में हल चलाया था—हालांकि यह नहीं कि रोटी की कमी थी, वह तो सारे संसार का दाता था। कानून इजाजत दे या नहीं, लेकिन उन्हें कम से कम इस सदन के जरिये सारे भारत के किसानों को विश्वास दिलाना चाहिए कि जालाबारी से जो नुकसान हुआ है, सरकार उस की क्षतिपूर्ति करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, आप डा० लोहिया के शिष्य रहे हैं। आप शेरों के नीचे बैठे हुए हैं। आप शेरों से दबने की बात न करें, बल्कि उन के पजों को पकड़ कर शरीबों की बात करें और बरनाला साहब को आदेश दें कि वह इस बारे में कुछ कहें।

15. 25 hrs.

*DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS), 1978-79

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up discussion and voting on the Demands for Grants in respect of the Budget (Railways) for 1978-79 for which 3 hours have been allotted.

Hon. Members whose cut motions to the Demands for Grants have been circulated, may if they desire to move